उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-8/2015/सा-3-जी0आई0-11/दस-2015-301/2000 टी0सी0
लखनऊ: दिनाँक : 08 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:-राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-16/सा-3-जी0आई0-18/दस-2014-301/2000 टी0सी0, दिनाँक 15 दिसम्बर, 2014, जिसके द्वारा महँगाई राहत दिनाँक 01 जुलाई, 2014 से 107 प्रतिशत स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय द्वारा औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस बीच हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 15 दिसम्बर, 2014 में उल्लिखित दरों का संशोधन करते हुए दिनाँक 01 जनवरी, 2015 से महंगाई राहत की 06 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- पेंशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में दिनाँक 01 जनवरी, 2015 से 06 प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की दर 107 प्रतिशत से बढ़कर 113 प्रतिशत हो जायेगी।

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3
No. 8 /2015/Sa-3-G.I.-11 /X-2015-301/2000 T.C.
Dated : Lucknow: 08 June, 2015

Office - Memorandum

Subject :Grant of dearness relief to State Government's civil / family pensioners.

The undersigned is directed to refer to the office memorandum No. 16/Sa-3-G.I.-18/X-2014-301/2000 T.C., dated December 15, 2014 on the above mentioned subject, sanctioning additional installment of dearness relief with effect from July 01, 2014 and to say that the Governor is pleased to further enhance by 06 percent, with effect from January 01, 2015, the rate of dearness relief admissible to all civil/ family pensioners of this Government to compensate them for the rise, in the meanwhile, in the average consumer price index.

2- As a consequence of the above-mentioned 06 percent rise, the dearness relief payable on the pension will rise from existing 90 107 percent to 113 percent with effect from January 01, 2015.

--2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नज़रअंदाज़ कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

4- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृष्ठांकन संख्या-7/2015/सा-3-जी0आई0-09/दस-2015-301/2000, दिनाँक 05 जून, 2015 द्वारा जारी कर दिया गया है।

5- यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

6- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनाँक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अत: पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-

3- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.

4- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings/ corporations etc. in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners / family pensioners have been issued vide endorsement number- 7/2015-G-3-G.I.-09/X-2015- 301/2000, dated - 05 June, 2015.

5- These orders will also be applicable to the pensioners of the institutions aided from State Fund, under the Education/ Technical Education Departments, whose pension / family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.

6- As per orders issued in O.M. No. A - 1- 252 / X- 10 (3)- 81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the

-3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

7- मँहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1)- उत्तर प्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

(2)- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं आडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(3)-महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.

7- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.

Neel Ratan Kumar
Special Secretary, Finance.

To,

(1)- All Principal Secretaries / Secretaries to Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

(2)- Accountant General (Account & Entitlement)-1,2 & Audit-1,2, Uttar Pradesh] Allahabad.

(3)- Office of Accountant General, Uttarakhand, Dehradun.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।